भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

23.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 662 का उत्तर

छत्तीसगढ़ में रेल पटरियों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

662. श्री विजय बघेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत कितने स्थानों पर रेल पटरियों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से संबंधित कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग से रावघाट वाया दल्लीराजहरा के बीच रेल पटरी के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास लंबित है;

(ग) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/कार्यान्वयन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/मंडलवार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़ वाली/संतृप्त लाइनों की क्षमता वृद्धि, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

समस्त रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित जोन-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। बहरहाल रायपुर मंडल में दोहरीकरण और विद्युतीकरण का विवरण निम्नानुसार है:

पिछले 5 वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 2683 करोड़ रुपए की लागत वाली 206 किलोमीटर लंबाई की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 1,931 कि.मी. कुल लंबाई वाली 31,619 करोड़ रुपए लागत की 26 परियोजनाएं (06 नई लाइनें और 20 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1023 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक 16,325 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। कार्य की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी.)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	6	609	184	6154
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	20	1323	839	10171
कुल	26	1931	1023	16325

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-2014	311 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-2026	6925 करोड़ रु. (22 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई रेल पटरियों की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन किए गए औसत रेलपथ
2009-14	32 कि.मी.	6.4 कि.मी प्रति वर्ष
2014-25	1189 कि.मी.	108.1 कि.मी. प्रति वर्ष (15 गुना से ज्यादा)

दल्लीराझरा-रावघाट नई लाइन (95 किलोमीटर) - दल्लीराझरा से ताड़ोकी (77 किलोमीटर) तक विद्युतीकरण सहित कार्य पूरा हो चुका है। ताड़ोकी से रावघाट (18 किलोमीटर) तक शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में, 3513 करोड़ रुपए की लागत से रावघाट-जगदलपुर नई लाइन (140 किलोमीटर) को भी मंजूरी दी गई है।

दोहरीकरण परियोजनाएँ लाइन क्षमता उपयोग और यातायात संभावना के आधार पर शुरू की जाती हैं। रेल परियोजनाओं को मंजूरी देना भारतीय रेल की सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है और रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान सम्पर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़ वाली/संतृप्त लाइनों का क्षमता विस्तार, सामाजिक-आर्थिक विचारों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है, जो चल रही परियोजनाओं की देनदारियों, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

रायपुर मंडल में विद्युतीकरण के साथ-साथ मल्टी-ट्रैकिंग के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

क्र.सं	खंड	कि.मी.	लागत (करोड़ रु में)
1	खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा 5वीं और 6वीं लाइन	278	8,741.38
2	रायपुर - टिटलागढ़ दोहरीकरण	203	1477.65
3	दुर्ग-राजनांदगांव के बीच चौथी लाइन	31	463.83

4	चौथी लाइन - दाधापारा- बिल्हा	9.2	169.06
5	चौथी लाइन - बिल्हा-दगोरी	6.5	86.59
6	निपनिया-भाटापरा	14.4	170.49
7	चौथी लाइन - भाटापारा-हथबंद	8.8	177.03
8	चौथी लाइन - भिलाई-दुर्ग लिंक केबिन	2.8	55.51
9	चौथी लाइन - भिलाई-भिलाईनगर	8.8	177.34
10	आरओआर/डागोरी-बेल्हा के बीच फ्लाई ओवर	8.18	156.03
11	उरकुरा-रायपुर स्टोर डिपो (आरएसडी) का दोहरीकरण	3	35.98
12	सरोना-भिलाई के बीच चौथी लाइन	17.30	290.47
13	दुर्ग लिंक केबिन-दुर्ग के बीच चौथी लाइन	3	143.17

किसी भी रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत साझेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा साझा लागत के भाग को जमा कराना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, जनोपयोगी बाधक सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लीयरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति आदि के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

****